





नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार कानून के दर्ये को व्यापक बनाया गया है। अब तीन साल से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अंदर लाया जाएगा। नई शिक्षा नीति बच्चों में जीवन जीने के जरूरी कौशल और जरूरी क्षमताओं को विकसित किए जाने पर जोर देती है। साथ ही बच्चों में पहली कक्षा से खुद का विकास करने का बोध भी उत्पन्न करती है।

भारत की प्राचीन शिक्षा आध्यात्मिकता पर आधारित थी। शिक्षा, मुक्ति एवं आत्मबोध के साधन के रूप में थी। भारत की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परंपरा विश्व इतिहास में प्राचीनतम है। डॉ अलटेकर के अनुसार, वैदिक युग से लेकर अब तक भारत वासियों के लिए शिक्षा का अभिप्राय यह रहा है कि शिक्षा प्रकाश का स्रोत है तथा जीवन के विभिन्न कार्यों में यह हमारा मार्ग आलोकित करती है। प्राचीन काल में शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया गया था भारत विश्वगुरु कहलाता था। विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा को प्रकाशस्रोत, अंतर्दृष्टि, ज्ञानचक्षु और तीसरा नेत्र आदि उपमाओं से विभूषित किया है। उस युग की यह मान्यता थी कि जिस प्रकार प्रकाश से अंधकार दूर होता है, उसी प्रकार व्यक्ति के सभी भ्रमों को दूर करने का साधन शिक्षा है। प्राचीन काल में इस बात पर बल दिया गया कि शिक्षा व्यक्ति को जीवन का यथार्थ दर्शन कराती है तथा इस योग्य बनाती है कि वह भवसागर की बाधाओं को पार करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सके जो कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में नीति में कहा गया है कि शिक्षा सबके लिए आवश्यक है, शिक्षा की सांस्कृतिक भूमिका है, शिक्षा वर्तमान और भविष्य के लिए अपने आय में एक अद्वितीय निवेश है।

20वां सदा का शुरुआत सांशेक्षणिकी का लकर समानता का मार्ग हानि लगी जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा वैचित्र समूह को समान अवसर उपलब्ध करवाना और शिक्षकों की शिक्षा, कार्य-प्रणाली, जिम्मेदारी, वेतन आदि सभी स्तरों पर गुणात्मक सुधार की आवश्यकता के साथ तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा को महत्व देने की बात होती रही। भारत की पहली शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी जिसमें वर्ष 1992 में बदलाव किए गए। बदलती जरूरतों के अनुसार शिक्षा नीति में परिवर्तन की दरकार लंबे समय से की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 सालों से शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। पहली बार नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय के लिए सार्वजनिक किया गया था और मंत्रालय को इस पर दो लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए।

गई शिक्षा नारा ने शिक्षा कर जापकर पानी पर चढ़ावर कर व्यापक बनाया गया है। अब तीन साल से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा कर

अधिकार कानून, 2009 के अंदर लाया जाएगा। अब कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा। नई शिक्षा नीति बच्चों में जीवन जीने के जरूरी कौशल और जरूरी क्षमताओं को विकसित किए जाने पर जोर देती है। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विश्वस्तरीय अनुसंधान और उच्च गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर जोर दिया गया है। अब हाइटर एजुकेशन में बल्ड कलास रिसर्च पर फोकस किया जाएगा। अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम का ढांचा भी बदला जाएगा। अब कोर्स के दौरान कक्षा से निकलने या प्रवेश करने के कई विकल्प दिए जाएंगे। पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल करने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिश की गई है।

जागरण ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भवित्व के सुन्दर व उत्तम राष्ट्रीय प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 को भारतीय लोगों, उनकी परंपराओं, संस्कृतियों और भाषाओं की विविधता को ध्यान में रखते हुए तेजी से बदलते समाज की जस्तियों के आधार पर तैयार किया गया है। शिक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए उच्च गुणवत्ता व व्यापक शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित की गई है। इसके जरिए भारत का निरंतर विकास सुनिश्चित होगा साथ ही वैश्विक मंचों पर आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, समानता और पर्यावरण की देखरेख, वैज्ञानिक उन्नति और सांस्कृतिक संरक्षण के नेतृत्व का समर्थन करेगा। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को

विद्याकालिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसा व्यावसायिक शिक्षाओं का इसके दायरे में लाया गया है।  
नई शिक्षा नीति में 10+2 के फार्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फार्मेट में हाला गया

गया हा। अब इस  $10+2$  से बाटकर  $5+3+3+4$  फार्मट में ढाला गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले पांच साल में प्री-प्राइमरी स्कूल के तीन साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फ्राउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले तीन साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद में तीन साल मध्य चरण (कक्षा 6 से 8) और माध्यमिक अवस्था के चार वर्ष (कक्षा 9

से 12)। स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा, छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहें ले सकते हैं। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि उच्चे शिक्षा में कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड अकैडमिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्त्व ता आदि शामिल है। नई शिक्षा नीति और सुधारों के बाद हम 2035 तक 50 फीसद सकूल नामांकन अनुपात प्राप्त करेंगे।

वहीं क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैस्प विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशनल साइंटफिक फोरम शुरू किया जाएगा। देश में 45 हजार कॉलेज हैं। ग्रेडेड स्वायत्तता के तहत कॉलेजों को शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता दी जाएगी। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। अभी हमारे यहां डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टैंडअलोन इंस्टिट्यूशंस के लिए अलग-अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होगा। बोर्ड परीक्षाओं के लिए कई प्रस्ताव नई एजुकेशन पॉलिसी में हैं। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व के कम किया जाएगा। इसमें वास्तविक ज्ञान की परख की जाएगी। कक्षा पांच तक मातृभाषा को निर्देशों का माध्यम बनाया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में सब चीजों की जानकारी होगी। बजट की घोषणा के समय नई शिक्षा नीति के लिए 99 हजार करोड़ रुपए दिया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट भाषण पढ़ते हुए कहा था कि इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार शिक्षा के लिए 99 हजार 300 करोड़ रुपए की बड़ी राशि खर्च करेगी।

अगर हम आन वाला चुनातया पर बात करता कारना काल में शिक्षण कार्य में बाधा के कारण ड्रॉपआउट दर में वृद्धि की आशंका है। जब स्कूल फिर से खुलेंगे तो बच्चों की वापसी सुनिश्चित करना और स्कूल में उनको बनाए रखना एक चुनौती होगी। वर्तमान महामारी ने तमाम सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है। महामारी को रोकने के प्रयास में अस्थायी रूप से शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। परिणामस्वरूप सभी छात्र कलासर्वम् शिक्षा से वंचित हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारों को अभी इस दिशा में बहुत लंबा रास्ता तय करना शेष है। परंतु निश्चित रूप से 'आत्मनिर्भर भारत' बनने की दिशा में यह एक बेहतर कदम है।

# Digit

संबंधों वाले प्रस्ताव को लेकर खासी हलचल है। दोनों मुल्कों के बीच प्रस्तावित साझेदारी में सिर्फ चार सौ अरब डालर का निवेश ही शामिल नहीं है, बल्कि इस साझेदारी से ईरानी बंदरगाहों पर चीन का प्रभाव और दखल भी काफी बढ़ने की संभावना है। फिलहाल दोनों मुल्कों के बीच आर्थिक-सैन्य साझेदारी संबंधी समझौते के प्रस्ताव पर भी विचार हो रहा है। हालांकि इसे अभी ईरानी संसद से मंजूरी नहीं मिली है। इसे ईरान के रणनीतिक खेल के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में इसी साल गष्ट्रपति चुनाव होने हैं। अगर चीन और ईरान के बीच इस प्रस्तावित साझेदारी पर सहमति बन जाती है तो भारतीय हित सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि मध्य एशिया से लेकर अफगानिस्तान तक में भारत में प्रवेश का रास्ता ईरान के दो महत्त्वपूर्ण बंदरगाह हैं।

भारत को परेशानी यह भी है कि ईरान ने भारत के सहयोग से बनाए जाने वाले चाबहार-जाहेदान रेल लाइन का निर्माण कार्य खुद शुरू कर दिया है। यह प्रस्तावित लाइन भारत के लिए अहमियत रखती है। रेल लाइन के सहारे भारत अफगानिस्तान के हाजीगंक तक व्यापारिक रस्ते को विकसित करने की योजना बना रहा है। लेकिन ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध इस रेल लाइन के विकास में भारतीय भागीदारी को लेकर बाधा बना हुआ है। ईरान-चीन के बीच साझेदारी संबंधी प्रस्ताव से यूरोपी देश और अमेरिका भी सतर्क हैं, क्योंकि साझेदारी पर सहमति बनने के बाद ईरान होरमुज जलडमरुमध्य के पास स्थित जस्क बंदरगाह चीन के हवाले कर सकता है। होरमुज जलडमरुमध्य तेल आपूर्ति का महतवपूर्ण रस्ता है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद ने ईरान को चीन की तरफ जाने को मजबूर किया है।

विरोधी स्वर उठे हैं। सबाल यह है कि दुनिया ईरान से एकतरफा उम्मीद क्यों लगाए बैठी है? पश्चिमी ताकतें चाहती हैं कि ईरान चीन के पाले में न जाए, लेकिन वे ईरानी अर्थव्यवस्था के संकट पर ध्यान देने को तैयार नहीं हैं। आखिर ईरान की मजबूरियां हैं। जिस प्रस्तावित सामरिक भागीदारी पर बातचीत रही है, उसकी शुरुआत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के 2016 में हुए ईरान दौरे के दौरान हुई थी। अब ईरान की मजबूरी है, क्योंकि अमेरिका ने 2018 के अंत में ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद ईरान का तेल निर्यात ढाई लाख बैरल रोजाना पर सिमट कर रह गया। जबकि बैन से पहले ईरान 25 लाख बैरल

ठांगे। ईरान यह समझ रहा है कि उसके साथ साझेदारी बढ़ाने में चीन सिर्फ अपना हित देख रहा है, वर्तोंकि इस चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध चरम पर पहुंच चुका है। चीन अगर ईरान के साथ साझेदारी बढ़ाएगा, तो उसकी पहुंच फारस की खाड़ी तक आसानी से हो जाएगी।

कल्प्या तल सुजाना भवात् फर्रा वा रह-सह कसर तेल की गिरती कीमतों ने पूरी कर दी। इससे ईरान के सामने गंभीर संकट खड़ा स्वाभाविक था। ईरान की चिंता उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा भी है। रेल, सड़क, नौवहन की बहुपक्षीय व्यवस्था वाले इस गलियारे को ईरान और मजबूत करने की कोशिशें करता रहा है। साल 2002 में इस गलियारे को पूरी तरह से विकसित करने के लिए ईरान, भारत और रूस के बीच सहमति बनी थी। गलियारे के विकास पर काम भी हुआ। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों ने गलियारे के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। भारत के मुंबई से ईरान के बंदर अब्बास, चाबहार के रास्ते अजरबैजान होते हुए रूस और यूरोप तक जाने वाला यह गलियारा ईरान के लिए खासा महत्वपूर्ण है। गलियारे का विस्तार प्रस्तावित चाबहार-जाहेदान रेल लाइन तक है। ईरान पर दोबारा अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद रूस इस गलियारे से संबंधित कुछ योजनाओं से पीछे हट गया। ईरान में अजरबैजान सीमा से तुर्कमेनिस्तान सीमा तक जाने वाली रेल लाइन का विद्युतीकरण

फर्रम का फान हूल्स रेलप के पास था, लाकन उसने काम शुरू नहीं किया।

पिछ्ले साल ईरानी राष्ट्रपति हसन रेहनी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने को लेकर बैठक भी हुई थी, मगर जमीन पर दोनों मुल्कों के बीच सिर्फ सीरिया में रणनीतिक सहयोग नजर आया। इसके पीछे रूस का स्वार्थ भी हो सकता है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का फायदा उठाते हुए रूस ईरान के हिस्से वाले अंतराष्ट्रीय तेल बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने लगा। इन बदले हालात का लाभ चीन उठा सकता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान में योजनाओं के विकास से भारत और रूस पीछे हटे हैं। चीन के अपने रणनीतिक स्वार्थ हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव परियोजना अगर उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे से जुड़ गई, तो इससे चीन और ईरान दोनों को लाभ मिलेगा। चीन ईरान के रास्ते यूरोपीय बाजार तक पहुंच सकेगा। साथ ही, ईरान के महत्वपूर्ण बंदरगाहों में घुसपैठ कर फारस की खाड़ी से अरब सागर तक अपना वर्चस्व बढ़ाएगा। हालांकि चीन-ईरान साझेदारी पर

# सत्यार्थ

**दबाव में भा आ जाएगा।**

# યવદાર સે મિલતા કે માન

रात गुजार सकते हैं। मैं अकेला हूँ, यहीं कहीं रात काट लूँगा। दंपती ने उसे धन्यवाद दिया व उस के कमरे में रात बिताई। सुबह जाते समय वे सोते हुए कलर्क को जगाना उचित न समझकर चले गए। इसके कई बर्षों बाद उस कलर्क को एक पत्र मिला जिसके साथ न्यूयार्क की फ्लाइट का टिकट था। जब कलर्क न्यूयार्क पहुंचा तो उसने पाया कि स्वागत में बर्षों पहले उसके कमरे में रात बिताने वाले वही महाशय खड़े थे। वह थे अमेरिका के दूसरे दिन वे उसे लेकर वेल्फोर्ड आस्टोरिया होटल पहुंचे और कलर्क से कहा कि आज से आप इस होटल के मैनेजर हो। कलर्क बोला-मैं मामूली से होटल में काम करने वाला क्या इतने बड़े होटल का प्रबंधन संभाल पाऊंगा? तब आस्टो ने कहा- तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे अंदर मानवता का ऐसा गुण है, जो सिर्फ असाधारण लोगों में ही हो सकता है। तुम्हारी विनम्रता, इंसानियत, करुणा व स्वयं तकलीफ सहने का भाव तुम्हें इस पद के योग्य बनाता है। वास्तव में सच ही कहा जाता है कि जो प्रतिष्ठा पैसे से हासिल नहीं होती है, वह हमें अपने व्यवहार से हासिल हो जाती है।



## आम आदमी पार्टी जालंधर के कार्यकर्ताओं द्वारा पंजाब सरकार के खिलाफ जहरीली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर प्रदर्शन

दर्शन लाल भगत ने वेस्ट हलके के विधायक के खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगाए



■ जालंधर ब्रीज ब्लूरो

आम आदमी पार्टी जालंधर वेस्ट की कार्यकर्ताओं ने बताया की उन्होंने सरकार द्वारा बनाये की पालना करते हुए बाबू जगजीवन राम चौक (बड़ीया मंडी) पर रोप प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन जहरीली और नकली शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ किया गया गया और जिन लोगों की मौतें हुई उनके प्रति संवेदना व्यक्त भी की गयी।

आम आदमी पार्टी जालंधर वेस्ट की तरफ से बाबू जगजीवन राम चौक (बड़ीया मंडी) पर रोप प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन जहरीली और नकली शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ किया गया गया और जिन लोगों की मौतें हुई उनके प्रति संवेदना व्यक्त भी की गयी।

वेस्ट हलके में दड़े-सटे, लॉटरी और नकली शराब का कारोबार सब विधायक की शह पर चल रहा है और इन पर रोप लगाने के लिए सरकार से मांग की और सरकार के अलग-अलग जाहों पर प्रदर्शन किए और साथ ही आम आदमी पार्टी वेस्ट से दर्शन लाल भगत ने वेस्ट हलके के विधायक के खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगाए और कहा

वेस्ट हलके में दड़े-सटे, लॉटरी और नकली शराब का कारोबार सब विधायक की शह पर चल रहा है और इन पर रोप लगाने के लिए सरकार से मांग की और सरकार के अलग-अलग जाहों पर प्रदर्शन किए और साथ ही आम आदमी पार्टी वेस्ट से दर्शन लाल भगत ने वेस्ट हलके के विधायक के खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगाए और कहा

## शिरोमणि अकाली दल एस.सी. विंग जालंधर द्वारा कांग्रेस सरकार के खिलाफ किया गया धरना प्रदर्शन

■ जालंधर ब्रीज ब्लूरो

आज गुरु रवि दाम चौक में शिरोमणि अकाली दल एस.सी. विंग जालंधर द्वारा कांग्रेस के खिलाफ किया गया धरना प्रदर्शन। यह प्रदर्शन जालंधर के शहरी प्रधान भजन लाल चोपड़ा और पूर्ण डिप्टी मेयर प्रवेश तांगड़ी की अगुवाई में हुआ। उन्होंने कहा की कांग्रेस सरकार ने दलित समाज के बच्चों को स्कूल-कार्लसिप भी नहीं दी जिन लोगों के नीले काठ नहीं थे उनके काट दिए गए हैं और बच्चों की स्कूल फीस भी माफ नहीं की गई। इस धरने में शामिल हुए जिता प्रधान कुलवंत सिंह मनन और पूर्व चेरामैन बलजीत सिंह नीला



■ जालंधर ब्रीज ब्लूरो

महल के मोंके पर पहुंच कर कहा नहीं मिल रहा। इस मोंके पर अशोक चंद्रलाल, बनवारी लाल, अरुण कुमार, हरप्रीत चोपड़ा, मनप्रीत चोपड़ा, कुलवंत कुमार, हैप्पी अबादपुरा आदि अन्य साथी मौजूद थे।

महल के मोंके पर पहुंच कर कहा की सरकार द्वारा दलित समाज के खिलाफ धरेशाही की जा रही है और सरकार ने जो सहूलतें दलित समाज को देनी थी वो सब कागजों में ही है असलियत में किसी को कुछ

महल के मोंके पर पहुंच कर कहा की सरकार द्वारा दलित समाज के खिलाफ धरेशाही की जा रही है और सरकार ने जो सहूलतें दलित समाज को देनी थी वो सब कागजों में ही है असलियत में किसी को कुछ

मिंटेंशों पर मिड डे मील के अधीन मेहनताने के लिए 2.5 करोड़ रुपए जारी

चंडीगढ़/ब्लूरो

पंजाब के स्कूल शिक्षा मंडी श्री विजय इंदर सिंगला के निंदेंशों पर मिड डे मील के मेहनताने के लिए 2.5 करोड़ रुपए के द्वारा की राशि जारी दी गई है, जिसमें मिड डे मील के अधीन रसोइयों / सहायकों को समय पर मेहनताना दिया जा सके। इसकी जानकारी दें हुए एक स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि शिक्षा मंडी के निंदेंश पर पंजाब मिड डे मील सोसाइटी द्वारा गंभीर एक फड़ जारी किए गए हैं। राज्य

के समूह जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए एक पत्र में इस मेहनताने का तुरंत वितरण करने और इसको कम्पोनेट के अनुसार खाता बही में दर्ज करने के भी प्रिंटिंग दिए गए हैं। प्रवक्ता के अनुसार द्वारे जिसने के अलावा लुधियाना जिले के लिए 22,03,200 रुपए, जालंधर के लिए 17,89,200 रुपए, पटियाला जिले के लिए 17,35,080 रुपए, अमृतसर के लिए 16,69,800 रुपए और संग्रहर के लिए 14,37,480 रुपए, जारी किए गए हैं।

पंजाब में नए रखे जाने वाले मुलाजमों के वेतन को लेकर पंजाब सरकार जो केंद्र द्वारा दिए गए हैं। पे-स्केल लागू करने जा रही है उसे भी तुरंत रद्द किया जाए। इसके साथ उन्होंने ने कहा मिड-डे-मिल के वर्करों का वेतन मई, जून और जुलाई वेतन तुरंत दिया जाए।

इस मोंके कुलदीप सिंह कौड़ा, गोविंद सिंह, अमनदीप सिंह, तरसेंग मधोपुर, मुलखाराज, संतोख सिंह, करमजीत सिंह, मनोहर लाल, अमरजीत सिंह आदि हाजिर हुए।

पंजाब में नए रखे जाने वाले मुलाजमों के वेतन को लेकर पंजाब सरकार जो केंद्र द्वारा दिए गए हैं। पे-स्केल लागू करने जा रही है उसे भी तुरंत रद्द किया जाए। इसके साथ उन्होंने ने कहा मिड-डे-मिल के वर्करों का वेतन मई, जून और जुलाई वेतन तुरंत दिया जाए।

इस मोंके पर अद्वितीय धरना के लिए 2.5 करोड़ रुपए जारी किया गया है।

पंजाब में नए रखे जाने वाले मुलाजमों के वेतन को लेकर पंजाब सरकार जो केंद्र द्वारा दिए गए हैं। पे-स्केल लागू करने जा रही है उसे भी तुरंत रद्द किया जाए। इसके साथ उन्होंने ने कहा मिड-डे-मिल के वर्करों का वेतन मई, जून और जुलाई वेतन तुरंत दिया जाए।

इस मोंके कुलदीप सिंह कौड़ा, गोविंद सिंह, अमनदीप सिंह, तरसेंग मधोपुर, मुलखाराज, संतोख सिंह, करमजीत सिंह, मनोहर लाल, अमरजीत सिंह आदि हाजिर हुए।

पंजाब में नए रखे जाने वाले मुलाजमों के वेतन को लेकर पंजाब सरकार जो केंद्र द्वारा दिए गए हैं। पे-स्केल लागू करने जा रही है उसे भी तुरंत रद्द किया जाए। इसके साथ उन्होंने ने कहा मिड-डे-मिल के वर्करों का वेतन मई, जून और जुलाई वेतन तुरंत दिया जाए।

इस मोंके कुलदीप सिंह कौड़ा, गोविंद सिंह, अमनदीप सिंह, तरसेंग मधोपुर, मुलखाराज, संतोख सिंह, करमजीत सिंह, मनोहर लाल, अमरजीत सिंह आदि हाजिर हुए।

पंजाब में नए रखे जाने वाले मुलाजमों के वेतन को लेकर पंजाब सरकार जो केंद्र द्वारा दिए गए हैं। पे-स्केल लागू करने जा रही है उसे भी तुरंत रद्द किया जाए। इसके साथ उन्होंने ने कहा मिड-डे-मिल के वर्करों का वेतन मई, जून और जुलाई वेतन तुरंत दिया जाए।

इस मोंके कुलदीप सिंह कौड़ा, गोविंद सिंह, अमनदीप सिंह, तरसेंग मधोपुर, मुलखाराज, संतोখ सिंह, करमजीत सिंह, मनोहर लाल, अमरजीत सिंह आदि हाजिर हुए।

पंजाब में नए रखे जाने वाले मुलाजमों के वेतन को लेकर पंजाब सरकार जो केंद्र द्वारा दिए गए हैं। पे-स्केल लागू करने जा रही है उसे भी तुरंत रद्द किया जाए। इसके साथ उन्होंने ने कहा मिड-डे-मिल के वर्करों का वेतन मई, जून और जुलाई वेतन तुरंत दिया जाए।

इस मोंके कुलदीप सिंह कौड़ा, गोविंद सिंह, अमनदीप सिंह, तरसेंग मधोपुर, मुलखाराज, संतोख सिंह, करमजीत सिंह, मनोहर लाल, अमरजीत सिंह आदि हाजिर हुए।

पंजाब में नए रखे जाने वाले मुलाजमों के वेतन को लेकर पंजाब सरकार जो केंद्र द्वारा दिए गए हैं। पे-स्केल लागू करने जा रही है उसे भी तुरंत रद्द किया जाए। इसके साथ उन्होंने ने कहा मिड-डे-मिल के वर्करों का वेतन मई, जून और जुलाई वेतन तुरंत दिया जाए।

इस मोंके कुलदीप सिंह कौड़ा, गोविंद सिंह, अमनदीप सिंह, तरसेंग मधोपुर, मुलखाराज, संतोख सिंह, करमजीत सिंह, मनोहर लाल, अमरजीत सिंह आदि हाजिर हुए।

पंजाब में नए रखे जाने वाले मुलाजमों के वेतन को लेकर पंजाब सरकार जो केंद्र द्वारा दिए गए हैं। पे-स्केल लागू करने जा रही है उसे भी तुरंत रद्द किया जाए। इसके साथ उन्होंने ने कहा मिड-डे-मिल के वर्करों का वेतन मई, जून और जुलाई वेतन तुरंत दिया जाए।

इस मोंके कुलदीप सिंह कौड़ा, गोविंद सिंह, अमनदीप सिंह, तरसेंग मधोपुर, मुलखाराज, संतोख सिंह, करमजीत सिंह, मनोहर लाल, अमरजीत सिंह आदि हाजिर हुए।

पंजाब में नए रखे जाने वाले मुलाजमों के वेतन को लेकर पंजाब सरकार जो केंद्र द्वारा दिए गए हैं। पे-स्केल लागू करने जा रही है उसे भी तुरंत रद्द किया जाए। इसके साथ उन्होंने ने कहा मिड-डे-मिल के वर्करों का वेतन मई, जून और जुलाई वेतन तुरंत दिया जाए।

इस मोंके कुलदीप सिंह कौड़ा, गोविंद सिंह, अमनदीप सिंह, तरसेंग मधोपुर, मुलखाराज, संतोख सिंह, करमजीत सिंह, मनोहर लाल, अमरजीत सिंह आदि हाजिर हुए।

पंजाब में नए रखे जाने वाले मुलाजमों के वेतन को लेकर पंजाब सरकार जो केंद्र द्वारा दिए गए हैं। पे-स्केल लागू करने जा रही है उसे भी तुरंत रद्द किया जाए। इसक